International Journal of Information Movement *Vol. 8 Issue IV* *(August 2023)*
Website: www.ijim.in *ISSN: 2456-0553 (online)* **Pages** **62-68**

हरियाणा में क्लाउड.आधारित ई.गवर्नेंसः डिजिलॉकर के संदर्भ में हिसार के छात्रों पर एक अध्ययन

कविता बैनिवाल
संवाददाता
जनसंचार विभाग, गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
और
डॉ मिहिर रंजन पात्र
जनसंचार विभाग गुरू जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा

सार : ई–गवर्नेंस सरकारी सेवाओं के लिए एक प्रौद्योगिकी–संचालित दृष्टिकोण है, जो सरकार और नागरिकों के बीच सूचना विनिमय, संचार लेनदेन और सिस्टम एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है। यह शोध अध्ययन क्लाउड आधारित ई–गवर्नेंस में डिजिलॉकर के संदर्भ में हिसार जिले के महाविद्यालय के विद्यार्थियों पर किया गया है। शोध का मुख्य उद्देश्य चयनित महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा डिजिलॉकर के उपयोग व संतुष्टि के बारें में दृष्टिकोंण का पता लगाना है। इसके अतिरिक्त डिजिलॉकर के बारे में जानकारी स्तर पता करना भी एक विशिष्ट उद्देश्य है। शोध के अंतर्गत सर्वेणक्ष विधि के माध्यम से तीन महाविद्यालयों के 300 छात्रों से प्रश्नावली टूल के माध्यम से प्रश्न पुछे गयें तथा उनका विश्लेषण किया गया है। शोध के विश्लेषण में पाया गया है कि उपयोग एवं संतुष्टि को लेकर सभी महाविद्यालय के छात्रों में संतुष्ट और असंतुष्ट में एक सार्थक अंतर पाया गया है। इसके अलावा डिजिलॉकर के बारे में दृष्टिकोण को लेकर भी संतुष्ट व असंतुष्ट छात्रों में एक सार्थक अंतर पाया गया है।

मुख्य शब्द : ई–गवर्नेंस, क्लाउड, दृष्टिकोंण, डिजिलॉकर

1.0 परिचय

हरियाणा एक उत्तर भारतीय राज्य है। इस राज्य की सीमा दक्षिण में राजस्थान और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और उत्तर में पंजाब और पूर्व में दिल्ली क्षेत्र से लगती है। चंडीगढ़ हरियाणा और पड़ोसी राज्य पंजाब की राजधानी भी है। इस राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। यह क्षेत्रफल के हिसाब से इसे भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य बनाता है। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम अधिनियम (1966) के तहत किया गया था। 23 अप्रैल 1966 को, पंजाब राज्य को विभाजित करने और नए हरियाणा राज्य की सीमाएँ निर्धारित करने के लिए, भारत सरकार ने जे.सी. शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग की स्थापना की। 31 मई 1966 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नल, गुड़गांव, रोहतक, महेंद्रगढ़ और हिसार जिलों को नए राज्य हरियाणा का हिस्सा बनाया गया। इसमें संगरूर जिले की जींद और नरवाना तहसीलें और नारानगढ़, अंबाला और जगाधरी तहसीलें भी शामिल थीं। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि चंडीगढ़ (पंजाब की राजधानी) में शामिल लेथ तहसील को भी हरियाणा में शामिल किया जाना चाहिए। जबकि हरियाणा में लेथ का एक छोटा सा हिस्सा ही शामिल था। चंडीगढ़ राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जो पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है।

हरियाणा दक्षिण–एशिया में सबसे अधिक आर्थिक रूप से विकसित क्षेत्र है, 1970 के दशक से कृषि और विनिर्माण में लगातार वृद्धि के साथ – राष्ट्रीय ई एंड गवर्नेंस योजना (NeGP) ने मिशन और मोड ई एंड गवर्नेंस परियोजनाओं को लागू करने पर जोर दिया है – हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को विभिन्न विभागों के लिए सुलभ बना दिया है, विभाग, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, हरियाणा राज्य केंद्र, और हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम – विभागीय आईटी कार्य योजनाओं की व्यवस्थित मंजूरी स्थापित करने के लिए उच्च शक्ति समितियों के माध्यम से एक सुलभ, पारदर्शी, और कुशल प्रणाली स्थापित की गई है – विभिन्न विभागों और संगठनों से 119 से अधिक आईटी और आधारित परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।

शासन में, लोगों को बातचीत करने और निर्णय लेने के लिए सेवाएं प्रदान करना, नागरिकों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करना, सार्वजनिक सेवाओं को वास्तविक लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और योजनाओं को तेजी से लागू करना शामिल है। सरकारों के लिए अपनी गतिविधियों के प्रति जवाबदेह होना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आर्थिक विकास का लाभ वास्तविक व्यक्ति तक पहुंचे। हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 का उद्देश्य सरकारी विभागों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, सेवा वितरण को बढ़ाना है। सार्वजनिक सेवा वितरण को सरल बनाने और प्रशासनिक मुद्दों में सुधार के लिए ई–गवर्नेंस की पहल शुरू की गई है। सिविल सेवा केन्द्र अभिमुखीकरण एवं पारदर्शिता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए शासकीय विभागों को कम्प्यूटरीकृत करने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

हरियाणा राज्य ने राष्ट्रीय ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क कार्यक्रम के तहत 5500 से अधिक गांवों तक पहुंचने के लिए ऑप्टिकल फाइबर निर्धारित किया है, जिससे सभी ग्राम पंचायतों के लिए 100 एमबीपीएस इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार ने गुणवत्तापूर्ण दूरसंचार सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए संचार एवं सूचना नीति लागू की है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की डिलीवरी के लिए ई–गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समिति के साथ, हरियाणा डिजिटल रूप से सक्रिय ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदल गया है। राज्य ने डिजिटल बुनियादी ढांचे, नागरिक सेवाओं के डिजिटल वितरण और नागरिक सशक्तिकरण में सुधार के लिए पहल की है।

2.0 हरियाणा राज्य में ई–गवर्नेंस पहल

सीएम विंडो: हरियाणा में सीएम विंडो हरियाणा ई–गवर्नेंस पहल का उद्देश्य शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करना है। 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किए गए इस पोर्टल का उद्देश्य सार्वजनिक शिकायतों का समाधान करना और अधिकतम शासन को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक शिकायतों की तत्काल सुनवाई सुनिश्चित करना और न्यूनतम प्रशासन को बढ़ावा देना है।

2.1 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हरियाणा : जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) ने कई ई–गवर्नेंस सेवाएं शुरू की हैं। इसमें एक कस्टम ईआरपी एकीकृत समाधान, पानी और सीवर (बीआईएसडब्ल्यूएएस) और सिविक हाउसिंग सेंटर (एसएनके) के लिए एक बिलिंग सूचना प्रणाली शामिल है।

2.2 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन: हरियाणा में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) ग्रामीण विकास दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए ऑनलाइन दवा सूची और हरियाणा की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली (ओडीआईएससीएम) सहित विभिन्न गतिविधियों को एकीकृत करता है। यह प्रणाली हरियाणा सरकार की नई दवा नीति के अनुरूप दवाओं की निरंतर उपलब्धता, गुणवत्ता नियंत्रण, खरीद और वितरण सुनिश्चित करती है।

2.3 हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग: हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन कार्ड प्रबंधन, आवंटन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और एफपीएस सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ई–गवर्नेंस लागू किया है। अंबाला में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिशन मोड प्रणाली के तहत 13 मिलियन से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित करती है, और डिजिटल राशन कार्ड के कारण हरियाणा राज्य केरोसिन अब मुफ्त है।

2.4 परिवहन नियामक कार्य: उप–विभागीय मजिस्ट्रेट कार्यालयों में परिवहन नियामक कार्य कम्प्यूटरीकृत ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र का उपयोग करते हैं, राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रणाली को एक मानक के रूप में अपनाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व संग्रह में वृद्धि होती है।

2.5 पब्लिक वैलफेयर डिपार्टमेंट: (पीडब्ल्यूडी): हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने ऑनलाइन बजट संचार, रिलीज, आवंटन, संशोधन और पुनर्विनियोग के लिए एक एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीडब्ल्यूडी) लागू की है। यह प्रणाली उत्तरदायी और जिम्मेदार शासन का प्रदर्शन करते हुए बजट तैयार करने के लिए आवश्यक समय को आठ महीने से घटाकर दो महीने कर देती है।

2.6 पर्यटन: हरियाणा पर्यटन निगम राजमार्ग पर्यटन में अग्रणी है, जो विभिन्न केंद्र संचालित करते है। उन्होंने सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के लिए 3बी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, ई–टिकटिंग के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली और वेब पोर्टल तैयार किया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि हरियाणा की पर्यटन आवश्यकताओं का पूरी तरह से ऑनलाइन उपयोग किया जा सके।

2.7 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग: सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग लाखों लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं प्रदान करता है। डीबीटी प्रणाली नौ ऑनलाइन योजनाएं प्रदान करती है, जिसमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन भत्ता, बच्चों के लिए वित्तीय सहायता (एफईडीसी), विकलांगता वाले गैर–स्कूली बच्चों के लिए समावेशी मुफ्त शिक्षा (एनएसजीडीसी), और चतुर लोगों के लिए बौद्ध और बच्चों के भत्ते शामिल हैं।

2.8 स्कूल एमआईएस पोर्टल: हरियाणा स्कूल एमआईएस पोर्टल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जिससे 20 लाख से अधिक छात्रों को विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश की सुविधा मिलेगी। पहले चरण में श्चेंज स्कूल एमआईएस पोर्टलश लॉन्च किया गया है, और अगले चरण में, प्रत्येक संस्थान, कार्यालय में स्वीकृत पदों, कर्मचारियों की कमी, पदों की कमी के लिए कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शिक्षक स्थानांतरण, एवं स्थानांतरण पोर्टल। इससे प्रशासनिक बोझ दूर होगा और शिक्षा विभाग को स्कूलों में शिक्षा मानकों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।

अन्य सेवायें: हरियाणा में राज्य सरकार ने ई–गवर्नेंस के तहत अपने नागरिकों की सेवा के लिए विभिन्न ई–सेवाएं शुरू की हैं। सभी जिलों में सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) खोले गए हैं, जो जल कनेक्शन, सीवर कनेक्शन, बिजली बिल संग्रह और राशन कार्ड सदस्यों जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। अन्य सेवाओं में पंजीकरण, एचबीएसई परिणाम, बोर्ड परीक्षा, प्रवेश पत्र, सरकारी कॉलेजों के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र, लंबी सड़क पुस्तक सत्र, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थिति और हुडा पूछताछ

फॉर्म शामिल हैं। आधार जन्म पंजीकरण लगभग सभी जिलों में किया जा रहा है, जिससे हरियाणा यह कार्य करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। डिजिटल इंडिया पहल के तहत एकीकृत उमंग ऐप पोर्टल हजारों पारंपरिक और ऑफलाइन सेवाएं 24/7 प्रदान करता है।

2.9 डिजीलॉकरः डिजीलॉकर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की एक डिजिटल इंडिया पहल है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनके डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके सशक्त बनाना है। सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल लॉकर सुविधाएं प्रदान करने वाले मध्यस्थों द्वारा सूचना का संरक्षण और प्रतिधारण) नियम, 2016 के नियम 9ए के अनुसार, डिजीलॉकर दस्तावेजों को मूल भौतिक दस्तावेजों के बराबर माना जाता है। अभी तक डिजीलॉकर के तहत 176.24 मिलियन यूजर ने अपना पंजीकरण करवा लिया तथा 5.92 बिलियन दस्तावेज अपलोड हो चुके है तथा हर रोज यह प्रकिया बढती जा रही है।

2.10 डिजीलॉकर के नागरिकों के लिये लाभः नागरिक सरकारी लाभ, रोजगार, वित्तीय समावेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए डिजिटल आदान–प्रदान और सहमति के साथ कभी भी, कहीं भी प्रामाणिक दस्तावेजों तक पहुंच सकते हैं।

2.11 डिजीलॉकर के एजेंसियों के लिये लाभः एजेंसियां कागज रहित शासन, कम प्रशासनिक ओवरहेड, डिजिटल परिवर्तन, सुरक्षित दस्तावेज गेटवे और वास्तविक समय सत्यापन से लाभ उठा सकती हैं। डिजीलॉकर विश्वसनीय जारी किए गए दस्तावेज प्रदान करता है, जबकि सुरक्षित दस्तावेज गेटवे नागरिक सहमति के साथ एक सुरक्षित दस्तावेज विनिमय मंच के रूप में कार्य करता है। वास्तविक समय सत्यापन सरकारी एजेंसियों को उपयोगकर्ता की सहमति प्राप्त करने के बाद सीधे जारीकर्ताओं से डेटा सत्यापित करने की अनुमति देता है।

2.12 क्लाउड–आधारित ई–गवर्नेंसः क्लाउड आधारित सेवायें क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा भंडारण, प्रबंधन और प्रसंस्करण के लिए स्थानीय सर्वर या पर्सनल कंप्यूटर के बजाय इंटरनेट पर दूरस्थ सर्वर का उपयोग करना शामिल है। क्लाउड प्रदाता उपयोग के आधार पर शुल्क लेते हैं, जिसमें ग्रिड और क्लस्टर आधार के रूप में काम करते हैं। आजकल इस तकनीकी का प्रयोग बड़ी तेजी से किया जा रहा है।

क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा भंडारण, प्रबंधन और प्रसंस्करण के लिए स्थानीय सर्वर या पर्सनल कंप्यूटर के बजाय इंटरनेट पर दूरस्थ सर्वर का उपयोग करना शामिल है। क्लाउड प्रदाता उपयोग के आधार पर शुल्क लेते हैं, जिसमें ग्रिड और क्लस्टर आधार के रूप में काम करते हैं।

3.0 शोध के उद्देश्यः

1. हिसार जिले के महाविद्यालय के छात्रों का डिजीलॉकर के बारे में जानकारी स्तर का पता लगाना
2. चयनित महाविद्यालयों के छात्रों में डिजीलॉकर के उपयोग व संतुष्टि के बारें में पता लगाना
3. महाविद्यालयों के छात्रों का डिजीलॉकर के बारें में दृष्टिकोण का पता लगाना।

4.0 शोध विधिः

शोधकर्ता ने यह शोध डिजीलॉकर के बारे में हिसार के महाविद्यालय के छात्रों पर एक अध्ययन किया है। शोधकर्ता ने छात्रों के चयन के लिये हिसार के तीन महाविद्यालयों को सुविधा नमूनाकरण पद्धति के आधार पर शोध के प्रदत हेतू जनसंख्या लिया है। ये तीन महाविद्यालय इस प्रकार हैः–

1. राजकीय महाविद्यालय, हिसार
2. डी.एन. महिविद्यालय, हिसार
3. सी.आर.एम. जाट महाविद्यालय, हिसार

उपर्युक्त महाविद्यालय में से एक महाविद्यालय सरकारी है तथा दो महाविद्यालय संस्था के अंर्तगत कार्य करते है। प्रत्येक महाविद्यायल में से शोधकर्ता ने 100 छात्रों को चयन प्रदत के रूप में किया है। कुल 300 छात्रों को प्रदत के रूप में चुना गया है। प्रत्येक महाविद्यालय से पुरूष तथा महिला छात्रों को चुना गया है तथा उनसे प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्नों के उतर जाने गये है। कुल 165 पुरूष तथा 135 महिला छात्रों को इस शोध में प्रदत के रूप में शामिल किया गया है। शोध पेपर में दोनों तरह स्वतंत्र व आश्रित का अध्ययन किया गया है। आयु, कक्षा श्रैणी तथा लिंग को स्वतंत्र चर के रूप में तथा ई–गवर्नेस के डिजीलॉकर के बारें में जानकारी, उसकी उपयोगिता तथा उसके बारें मे दृष्टिकोण को आश्रित चर के रूप में लिया है।

यह शोध एक संख्यात्मक शोध डिजाइन पर आधारित है। शाधकर्ता ने प्रतिशत तथा माध्यम सांख्याकीय विधियों का प्रयोग प्रदत के आंकलन हेतु किया है। इसके अतिरिक्त काईस्क्यौर (chi-square) का प्रयोग प्रदत में कोई महत्वपूर्ण अंतर को मापने के लिये किया है। प्रदत के विश्लेषण हेतु एम.एस. एक्सल सॉफवेयर का प्रयोग किया गया है।

4.1 आंकड़ों का विश्लेषण व शोध परिणाम :

आंकडों का विश्लेषण में शोधकर्ता ने उत्तरदाताओं से प्राप्त उत्तरों का विश्लेषण किया है। शोधकर्ता ने तालिका का निमार्ण तथा तालिकाओं का विवरण दिया है। विभिन्न चर के आधार पर तालिकाओं को निर्मित किया है तथा उनकी व्याख्या की है।

4.2 प्रदत के स्वतंत्र चर बारे विश्लेषण –

तालिका 1. ***स्वतंत्र चर की जानकारी***

क्रमांक	**महाविद्यालय का नाम**	**आयु श्रैणी**	**संख्या**	**लिंग**		**प्रतिशत**		
				पुरूष	**महिला**	**पुरूष**	**महिला**	**कुल**
1.	*राजकीय महाविद्यायल*	15–20	55	31	24	10.33	08	1833
		20–30	40	24	16	08	5.33	13.33
		30 से उपर	05	03	02	01	0.66	1.66
	कुल		100	58	42	19.33	13.99	42.32
2.	*डी.एन. महिविद्यालय*	15–20	60	30	30	10	10	20
		20–30	37	22	15	7.33	05	12.33
		30 से उपर	03	02	01	0.66	0.33	01
	कुल		100	54	46	17.99	15.33	33.33
3.	*सी.आर.एम. जाट महाविद्यालय*	15–20	57	29	28	9.66	9.33	19
		20–30	40	22	18	7.33	06	13.33
		30 से उपर	03	02	01	0.66	0.33	01
	कुल		100	53	47	17.65	15.66	33.33
कुल योग			**300**	**165**	**135**	**54.97**	**45.03**	**100**

स्रोत फिल्ड सर्वे

उपरयुक्त तालिका संख्या 1 में स्वतंत चर का विश्लेषण किया गया है। सभी चयनित महाविद्यालयों के उत्तरदाओं का उनकी आयु तथा उनके लिंग के आधार पर विवरण दिया गया है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 179 पूरूष तथा 129 महिला उत्तरदाताओं ने भाग लिया जोकि कुल का क्रमनुशार 54.97 प्रतिशत तथा 45.03 प्रतिशत पाये गये। सभी चयनित महाविद्यालयों में पुरूष उत्तरदाता जोकि 15–20 आयुवर्ग के है कि संख्या सबसे अधिक पाई गई। सभी चयनित महाविद्यालयों में पुरूष छात्रों की संख्या महिला छात्रों की संख्या से ज्यादा पाई गई। Chi-Square test की सहायता से सभी चयनित महाविद्यालय के पुरूष ओर महिला छात्रों का p value (probalitity vlue) का पता लगया गया जोकि 0.0832 प्राप्त हुआ। क्योकि पी का मान 0.05 ($p > 0.05$) से ज्यादा पाया गया है, इसलिए पुरूष और महिला छात्रों की संख्या में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

4.3 प्रदत के आश्रित चर बारे विश्लेषण –

तालिका 2. **डिजीलॉकर के बारे में जानकारी स्तर–**

क्रमांक	**महाविद्यालय का नाम**	**लिंग**	**संख्या**		**प्रतिशत**	
			हां	**नहीं**	**हां**	**नहीं**
1.	*राजकीय महाविद्यायल*	**पुरूष**	45	13	27.27	9.63
		महिला	18	24	10.91	17.78
	कुल		63	37	38.18	27.41
2.	*डी.एन. महिविद्यालय*	**पुरूष**	46	08	27.88	5.93

		महिला	20	26	12.12	19.26
	कुल		66	34	40.00	25.19
3.	*सी.आर.एम.जाट महाविद्यालय*	**पुरूष**	40	13	24.24	9.63
		महिला	22	25	13.33	18.52
	कुल		62	38	37.58	28.15
कुल योग			**191**	**109**	..	..

तालिका संख्या 2 में दर्शाया गया है कि चयनित महाविद्यालय के विद्यार्थियों को डिजीलॉकर के बारें में जानकारी है या नहीं। विश्लेषण के बाद पाया गया कि महिला छात्रों की अपेक्षा पुरूष छात्रों को डिजीलॉकर के बारे में जानकारी हैं। डी.एन. महाविद्यालय के छात्रों में पुरूष छात्रों को अन्य दो महाविद्यालयों के पुरूष छात्रों से डिजीलॉकर के बारे में ज्यादा जानकारी है। Chi-Square test के विश्लेषण से पता चलता है कि सभी चयनित महाविद्यालयों के छात्रों में पुरूष तथा महिला छात्रों के जानकारी स्तर में एक सार्थक अंतर पाया गया है जोकि $p < 0.05$ है। p का मान 0.0025 पाया गया जिससे स्पष्ट है कि दोनों श्रेणियों के जानकारी स्तर में एक सार्थक अंतर है।

तालिका 3. **डिजीलॉकर के उपयोगिता व संतुष्टि स्तर के बारे विश्लेषण–**

कंमाक	**महाविद्यालय का नाम**	**लिंग**	**संख्या**			**प्रतिशत**		
			संतुष्ट	**असंतुष्ट**	**पता नहीं**	**संतुष्ट**	**असंतुष्ट**	**पता नहीं**
4.	*राजकीय महाविद्यायल*	**पुरूष**	40	05	13	66	8.25	21.45
		महिला	15	03	24	20.25	4.05	32.4
	कुल		55	08	37	86.25	12.3	53.85
5.	*डी.एन. महिविद्यालय*	**पुरूष**	44	02	08	72.6	3.3	13.2
		महिला	15	05	26	20.25	6.75	35.1
	कुल		59	07	34	92.85	10.05	48.3
6.	*सी.आर.एम.जाट महाविद्यालय*	**पुरूष**	35	05	13	57.75	8.25	21.45
		महिला	18	04	25	24.3	5.4	33.75
	कुल		53	09	38	82.05	13.65	55.2
कुल योग			168	23	109	..	..	

उपरयुक्त तालिका में उत्तरदाताओं का उपयोग एंव संतुष्टि से संबधित डाटा दर्शाया गया है। यह पाया गया है कि सबसे अधिक डी.एन. महाविद्यालय से पुरूष छात्र है संतुष्ट पाये गये जोकि कुल पुरूष छात्रों का 72.6 प्रतिशत है। महिला छात्रों में सबसे अधिक संतुष्ट छात्र सीआरएम जाट महाविद्यालय से मिले जो कुल महिला छात्रों का 27 प्रतिशत है। यह पाया गया कि जिन छात्रों को डिजीलॉकर की जानाकारी नहीं है तो वो इसे उपयोग भी नहीं करते है तथा उन्होंने पता नहीं उतर अपने प्रतिउतर में दिया। गई। Chi-Square test की सहायता से सभी चयनित महाविद्यालय के पुरूष ओर महिला छात्रों का p value (probalitity vlue) का पता लगया गया। पी का मान 1.322 पाया गया जिससे ये साबित होता है कि संतुष्ट तथा असंतुष्ट छात्रों में एक सार्थक अंतर पाया गया है। संतुष्ट छात्र की संख्या असंतुष्ट छात्रों से ज्यादा है। इसके अतिरिक्त संतुष्ट तथा पता नहीं में सार्थक अंतर पाया गया है, इनके लिये पी का मान 0.0025 पाया गया।

तालिका 4. ***दृष्टिकोण संबधित विश्लेषण –***

कंमाक	**महाविद्यालय का नाम**	**थ्लंग**	**संख्या**			**प्रतिशत**		
			धनात्मक	**ऋणात्मक**	**उदासीन**	**धनात्मक**	**ऋणात्मक**	**उदासीन**
7.	*राजकीय*	**पुरूष**	39	06	13	64.35	9.9	21.45

	महाविद्यायल	**महिला**	14	04	24	18.9	5.4	32.4
	कुल		53	10	37	83.25	15.3	53.85
8.	*डी.एन. महिविद्यालय*	**पुरूष**	40	06	08	66	9.9	13.2
		महिला	16	04	26	21.6	5.4	35.1
	कुल		56	10	34	87.6	15.3	48.3
9.	*सी.आर.एम.जाट महाविद्यालय*	**पुरूष**	37	03	13	61.05	4.95	21.45
		महिला	20	02	25	27	2.7	33.75
	कुल		57	05	38	88.05	7.65	55.2
		कुल योग	**166**	**25**	**109**	..	..	

उपयुक्त तालिका में महाविद्यालय के छात्रों का डिजीलॉकर के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। यह पाया गया कि पुरूष छात्र डिजीलॉकर के प्रति महिला छात्रों की अपेक्षा धनात्मक दृष्टिकोण रखते है। सबसे ज्यादा डीएन महीविद्यालय के पुरूष छात्रों का दृष्टिकोण धनात्मक पाया गया जोकि कुल पुरूष छात्रों का 66 प्रतिशत पाया गया। महिला छात्रों में धनात्मक दृष्टिकोण सबसे अधिक सीआरएम जाट महाविद्यालय की महिलाओं का प्रतिशत सबसे अधिक पाया गया जोकि कुल महिला छात्रों का 27 प्रतिशत था। Chi-Square test से दृष्टिकोण को लेकर पी के मान का पता लगाया गया। यह पाया गया कि दृष्टिकोण को लेकर पी का मान 2.863 पाया गया जिससे यह स्पष्ट है कि धनात्मक व ऋणात्मक दृष्टिकोण रखने वाले छात्रों में एक सार्थक अंतर है। तालिका में दर्शाया गया है कि धनात्मक दृष्टिकोण रखने वाले छात्र ऋणात्मक दृष्टिकोण रखने वाले छात्रों से 47 प्रतिशत अधिक है।

5.0 सारांशः

शोध ' हरियाणा में क्लाउड–आधारित ई–गवर्नेंसः डिजिलॉकर के संदर्भ में हिसार के छात्रों के पर एक अध्ययन' में यह पाया गया कि महाविद्यालय के छात्रों में डिजिलॉकर को लेकर जानकारी का अभाव है। जानकारी को लेकर निकाले गये पी मान से स्पष्ट है कि डिजिलॉकर के बारे में जानने वाले तथा न जानने वाले छात्रों में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है। हांलाकि जानकारी रखने वाले छात्रों की संख्या जानकारी न रखने वाले छात्रों से अधिक पाई गई फिर भी दोनों में एक सार्थक अंतर पाया गया। यह भी है कि महिला छात्रों की जानकारी का स्तर पुरूष छात्रो के स्तर से कम पाया गया।

उपयोग व संतुष्टि को लेकर यह पाया गया कि जानकारी रखने वाले छात्र डिजिलॉकर से संतुष्ट है तथा इसका उपयोग भी करते है। संतुष्ट तथा असंतुष्ट छात्रों में एक सार्थक अंतर पाया गया है। संतुष्ट व असंतुष्ट छात्रों में यह कहा जा सकता है कि डिजिलॉकर के उपयोग को लेकर सभी उपयोग करने वाले छात्र इससे संतुष्ट है।

दृष्टिकोण के बारे में यह पाया गया कि सभी छात्रों में धनात्मक तथा ऋणात्मक दृष्टिकोण को लेकर एक सार्थक अंतर है। धनात्मक दृष्टिकोण रखने वाले छात्रों की संख्या ऋणात्मक दृष्टिकोण रखने वाले छात्रों से ज्यादा पाई गई है।

6.0 संदर्भ सूचीः

1. Department of Social Justice and Empowerment, Government of Haryana, India website (2018), Retrieved from http://www.socialjusticehry.gov.in/en-US.
2. E-Governance in Haryana, Department of Information Technology Electronics & Communication, Haryana(2018), Retrieved from http://haryanait.gov.in/en/e-governance-in-haryana.
3. Excise and taxation department of Haryana website (2018), Retrieved from http:// www.haryanatax.gov.in.
4. Food Civil Supplies & Consumer Affairs Department Haryana website (2018), Retrieved from http://haryanafood.gov.in/en-us.
5. Haryana CM window-register complaints here (2018), Retrieved from http://www.dnaindia.com/ locality/faridabad/now-know-your-your-complaint-status-online-cm-window-49928.
6. Haryana e-District Services | National Government Services (2018), Retrieved from https:// services.india.gov.in/service/detail/haryana-e-district-services-1.
7. Haryana launches 4 major digital initiatives (2018), Retrieved from https://www.dailypioneer.com/ 2015/state-editions/haryana-launches-4-major-digital-initiatives.html.
8. Haryana rajyakaitihashaurjankari (2018), Retrieved from https://www.gyanipandit.com/haryanahistory information.

9. Haryana Tourism (2018), Retrieved from http://haryanatourism.gov.in.
10. Haryana: Promising Initiatives in Finance, e-Governance (2018), Retrieved from http:// inclusion.skoch.in/story/802/haryana-promising-initiatives-in-finance-egovernance1102.html.
11. https://www.digilocker.gov.in/
12. Implementing National e-Governance Plan in Haryana Article (2018), Retrieved from http:// egov.eletsonline.com/2007/07/implementing-national-e-governance-plan-in-haryana.
13. Implementing National e-Governance Plan in Haryana Article (2018), Retrieved from http://egov.eletsonline.com/2007/07/implementing-national-e-governance-plan-in-haryana.
14. Implementing National e-Governance Plan in Haryana Article (2018),Retrieved from http:// egov.eletsonline.com/2007/07/implementing-national-e-governance-plan-in-haryana.
15. National Agriculture Market (2018), Retrieved from https://enam.gov.in/web/. Transport Department Govt. of Haryana website (2018) Retrieved from https://haryanatransport.gov.in/#content